अखबार वो जो दिखाता है सच

हिन्दी दैनिक

तेजयुग न्यूज़

स्थापना दिवस 2024

www.tejyug.com

• वर्ष/year : 01 • अंक/issu : 73 • पृष्ठ/page 12 • मूल्य/rate : 3 ₹

• गुरुवार, 14 मार्च, 2024
• Thursday, 14 March, 2024

हापुड़ से प्रकाशित/ Published From Hapur

UPHIN/2023/51292

पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन चिप संयंत्रों की रखी आधारशिला

आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्ज्वल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे है

तेजयुग न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं को शुरू होने में सिर्फ 15 दिन लगे हैं।

फरवरी में, प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम के तहत तीन और सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी। 21 दिसंबर, 2021, कुल परिव्यय 76,000 करोड़ रुपये के साथ। चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह, खासकर देशभर से आए हजारों छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज, हम न केवल इतिहास फिर से लिख रहे हैं बल्कि उज्ज्वल भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग भी लगा रहे हैं।

यह ऐतिहासिक दिन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र बनने में

मदद करेगा। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। 60,000 से अधिक कॉलेज, विश्वविद्यालय और संस्थान वस्तुतः इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रधान मंत्री ने कहा, हाई-एंड चिप्स के बिना 21वीं सदी की कल्पना नहीं की जा सकती है और भारत उद्योग 4.0 क्रांति में सभी स्पेक्ट्रम में सेमीकंडक्टर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, गुजरात में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी गई। मोरीगांव, असम में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा; और साणंद, गुजरात में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा है।

तीन नए चिप प्लांट में से दो गुजरात में और एक असम में स्थापित किया जा रहा है। इन तीन प्लांट में से दो टाटा ग्रुप लगा रहा हैष गुजरात के धोलेरा में पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (पीएसएमसी), ताइवान के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। इस फैब में 91,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। सीजी पावर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जापान और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, थाईलैंड के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगा। यह इकाई 7,600 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी। सीजी पावर सेमीकंडक्टर यूनिट उपभोक्ता, औद्योगिक, ऑटोमोटिव और बिजली अनुप्रयोगों के लिए चिप्स का निर्माण करेगी। असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स उत्पादन की क्षमता वाली यह सुविधा 27,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। जिन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा उनमें ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता। इन इकाइयों से 20 हजार उन्नत प्रौद्योगिकी नौकरियों का प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 60 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, दूरसंचार विनिर्माण, औद्योगिक विनिर्माण और अन्य सेमीकंडक्टर-उपभोक्ता उद्योगों में रोजगार सृजन में तेजी लाएंगी।

चिप निर्माण विकास के रास्ते खोलेगी : पीएम

पीएम मोदी ने आगे कहा कि चिप निर्माण सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है, जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है।

एसबीआई के अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत को सूचित किया

हर सूचना को सार्वजनिक करेंगे : मुख्य चुनाव आयुक्त

तेजयुग न्यूज

नईदिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि चुनाव निकाय समय पर चुनावी बांड पर सभी विवरणों का खुलासा करेगा। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, कुमार ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड विवरण कल (12 मार्च) समय पर सौंप दिया है। कुमार ने कहा, मैं वापस जाऊंगा, डेटा देखूंगा और निश्चित रूप से समय पर इसका खुलासा करूंगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग पारदर्शिता के पक्ष में रहा है। उनका यह बयान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका के कुछ घंटों बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में कहा गया है कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बांड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, हमने अदालत में कहा कि हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं। आयोग में हम जो कुछ भी करते हैं और चुनाव प्रक्रिया में हमारे जिला मजिस्ट्रेट भी जो कुछ भी करते हैं वह खुलासे पर आधारित होता है हर बात का खुलासा करना। आयोग हमेशा पारदर्शिता के पक्ष में रहा है और चुनावी बांड मामले में भी हमारा रुख यही था।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद करने का भी आदेश दिया था। अदालत ने एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था, जिसमें नकदीकरण की तारीख और चुनावी बांड का मूल्य 6 मार्च तक शामिल होगा। चुनाव आयोग को अपने आधिकारिक पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए कहा गया था। एसबीआई ने कहा कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बांड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 की अवधि के दौरान कुल 22,217 बांड खरीदे गए थे। हलफनामे में बताया गया है कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल, 2019 तक खरीदे गए चुनावी बांड की कुल संख्या 3346 थी और भुनाए गए बांड की कुल संख्या 1609 थी।

हापुड़ **पारा** अपडेट

मैक्सिमम	मिनीमम
22.00 °C°C	11.00 °C°C

सूर्यास्त (आज) ›› 17 .10 बजे

सूर्योदय (कल) ›› 06 .25 बजे

खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने की घोषणा की। श्री खट्टर ने यह घोषणा विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान की। उन्होंने कहा कि वह आज करनाल विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा क्षेत्र की देखरेख करें। उन्होंने कहा कि संगठन (भाजपा) की तरफ से जो कार्य मिलेगा, वह करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें भरपूर स्नेह देने के लिये हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त किया। श्री खट्टर ने मंगलवार को ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और शाम को श्री सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजनीतिक हल्कों में ऐसी चर्चा है कि वह लोकसभा चुनाव में करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं।

रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले का मुख्य संदिग्ध हिरासत में

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुख्य संदिग्ध को हिरासत में लिया है। एनआईए को यह सफलता संदिग्ध की तस्वीर साझा करने और सूचना देने वाले को 10 लाख रुपये के इनाम की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद मिली। गत 01 मार्च को घटना वाले दिन संदिग्ध की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसमें वह कैफे के अंदर इडली की प्लेट ले जाता दिख रहा था। उसे कंधे पर रखे बैग के साथ देखा गया, जिसके अंदर आईईडी बम रखे होने का संदेह व्यक्त किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य संदिग्ध की पहचान शब्बीर के रूप में हुई है, जिसे बल्लारी जिले के चॉल बाजार इलाके से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारी विस्फोटों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के बीच तारतम्य की जांच कर रहे हैं।

पद्मश्री विजेताओं को प्रति माह 25 हजार रुपए : नवीन

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को प्रति माह 25,000 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के सूत्रों ने कहा कि राज्य में प्रत्येक पद्म पुरस्कार विजेता को समाज में उनके बेहद योगदान के लिए 25,000 रुपये मासिक सम्मान राशि मिलेगी। यह योजना अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। श्री पटनायक ने कहा कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान से देश को गौरवान्वित किया है।

भाजपा ने तोड़ा लद्दाख की जनता का भरोसा : प्रियंका गांधी

नयी दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मांग को जायज ठहराते हुए बुधवार को कहा कि सरकार को लद्दाख ताकि संवेदनशीलता को देखते हुए वाजिव मांग को पूरा करना चाहिए। श्रीमती वाड्रा ने कहा कि शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले आठ दिन से भूख हड़ताल पर हैं और जिस जगह उनका अनशन चल रहा है वहां तापमान शून्य से 15 डिग्री नीचे है। उनका कहना था कि सरकार को लद्दाख की जनता के साथ धोखा किए बिना क्षेत्र में बढ़ रही चीनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। श्रीमती वाड्रा ने कहा, भाजपा ने लद्दाख की जनता से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया।

यूक्रेन में भारतीयों को जबरन भेजे जाने की जांच जारी

सीबीआई मामले में आरोपी प्राइम मध्य प्रदेश में एक भाजपा पार्षद का बेटा

तेजयुग न्यूज

नईदिल्ली: यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में भारतीयों को कथित तौर पर धकेलने के लिए छात्र वीजा का दुरुपयोग करने के मामले में सीबीआई मामले में आरोपी प्राइम मध्य प्रदेश में एक भाजपा पार्षद का बेटा है।

मामले के आरोपी सुयश मुकुट की मां अनीता मुकुट धार नगर परिषद में भाजपा की निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। धार के मुख्य नगर अधिकारी निशिकांत शुक्ला ने कहा, नगरसेवक के रूप में यह उनका पहला कार्यकाल है। सूत्रों ने कहा

कि परिवार इंदौर से था और धार में बस गया जहां सुयश के पिता रमाकांत मुकुट एक स्थानीय अस्पताल में सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करते हैं। संयोग से, परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई तस्वीरें हैं।

संपर्क करने पर, भाजपा के धार जिला अध्यक्ष, मनोज सोमानी ने कहा कि उन्हें रिपोर्टों से मुकुट के बेटे के खिलाफ सीबीआई मामले के बारे में पता चला। जब मैंने पिछले साल (जिले का) कार्यभार संभाला था तब वह पहले से ही निगम पार्षद थीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। जबकि सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि एजेंटों ने रूस में संदिग्ध विश्वविद्यालयों में प्रवेश के बहाने भारतीयों को धोखा दिया, लेकिन इसमें संस्थानों का नाम नहीं बताया गया।

अंतिम सर्वेक्षण के लिए श्रीनगर पहुंची चुनाव आयोग की टीम

विधानसभा का चुनाव भी साथ कराने की मांग

तेजयुग न्यूज

श्रीनगर: यहां के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने आज भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से लोकसभा चुनाव के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अन्य अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंचे। पैनल ने आगामी आम चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए हितधारकों के साथ दो दिवसीय बैठक शुरू किया।

पैनल के सदस्यों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम वानी, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए ईसीआई पर दबाव डाला।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने आयोग को बताया कि 10 साल हो गए हैं जब जम्मू-कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं। इसलिए, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। आयोग ने हमें धैर्यपूर्वक सुना है। उन्होंने कहा कि एक साल में दो अलग-अलग चुनाव कराने से जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। यहां पर्यटन क्षेत्र बहुत जीवंत है और लोग पर्यटकों की भारी भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए, यदि एक वर्ष में दो चुनाव (अलग-अलग) होते हैं, तो आर्थिक गतिविधि बाधित हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री का सपना है कि एक देश, एक चुनाव हो। तो इसकी शुरूआत जम्मू-कश्मीर से क्यों न की जाए। वानी ने कहा कि पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि यहां लोगों को आशंका है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।

सीएए को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दाखिल

असम में अनेक संगठन इस फैसले के खिलाफ

तेजयुग न्यूज

गुवाहाटी : असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने के नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया। उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को भी चुनौती दी। सैकिया ने अपने तर्क में बताया कि दोनों नियम और उनके मूल अधिनियम धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शायरा बानो वी यूनियन ऑफ इंडिया (2017) 9 एससीओ 1 मामले में उल्लिखित 'प्रकट मनमानी' परीक्षण को पूरा करने में विफल है।

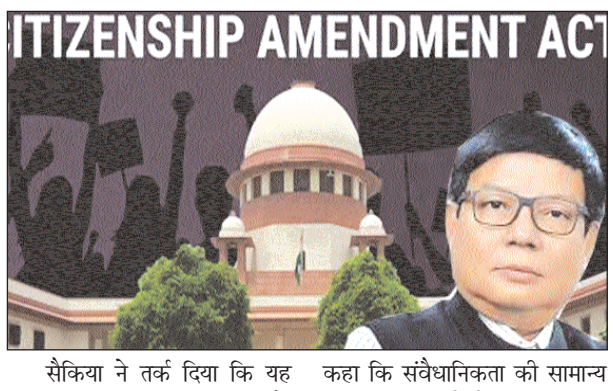

सैकिया ने तर्क दिया कि यह वर्गीकरण अनुचित, भेदभावपूर्ण है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है और यह पक्षपात या भाई-भतीजावाद से ग्रस्त है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत उपचार के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिकता की सामान्य धारणा इस मामले में लागू नहीं की जा सकती। सैकिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, जो नागरिकता की स्थिति के बावजूद सभी व्यक्तियों को समानता की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, सैकिया ने जोर देकर कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम असम समझौते के खंड 6 का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि 31 दिसंबर, 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों को नागरिकता देकर, अधिनियम सीधे तौर पर 1985 के असम समझौते की शर्तों का खंडन करता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे उपाय खतरे में पड़ सकते हैं असम राज्य की नाजुक जातीयता और सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना।सैकिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) दायर की है, जिसमें 2019 में अधिनियम के अधिनियमन और साढ़े चार साल से अधिक समय तक इसके कार्यान्वयन न होने का हवाला दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान रिट याचिका पर अदालत के अंतिम निर्णय तक कार्यान्वयन में देरी से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले सोमवार शाम को सीएए लागू करने के नियमों की घोषणा की। अधिनियम का उद्देश्य उत्पीड़न का सामना कर रहे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए।

चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति के पहले विपक्ष के नेता ने पत्र लिखा

अधीर रंजन ने चयनित लोगों के नामों की सूची मांगी

तेजयुग न्यूज

नईदिल्ली: दो चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली चयन समिति की गुरुवार को बैठक होने वाली है, तीन सदस्यीय पैनल में विपक्षी सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को पत्र लिखकर जिन नामों पर चर्चा होने वाली है, उनकी सूची मांगी है। इसमें संबंधित व्यक्तियों के डोजियर की मांग की गयी है। समझा जाता है कि केंद्रीय कानून और न्याय

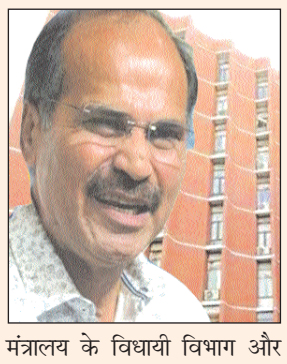

मंत्रालय के विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के सचिव राजीव मणि को लिखे एक पत्र में, चौधरी ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों और प्रमुखों के चयन के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया है। सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों ने सरकार से समान प्रक्रिया का पालन करने को कहा। लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में, चौधरी प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाले पैनल के सदस्य भी हैं जो सीआईसी और सीवीसी का चयन करते हैं।